RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2016-2018 IPT indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE ■ 29 AUGUST TO 04 SEPTEMBER 2018 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 04 ■ अंक 01 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

इंदौर से पहली अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा दिसंबर तक संभव

Page 3

बड़े संकेत जो बताते हैं कि भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है

Page 4

रॉयल एनफील्ड: Classic 350 का ये स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च

Page 7

editoria!

दिवालिया होतीं कंपनियां

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था एक बड़ी परीक्षा के दौर से गुजर रही है। रिजर्व बैंक के नए निर्देशों के मुताबिक करीब 70 कंपनियों को अपना कर्जा चुकाने की व्यवस्था करने के लिए 180 दिनों की जो मोहलत दी गई थी, वह आज यानी 27 अगस्त दिन सोमवार को खत्म हो रही है। कुछ कंपनियों ने इस दौरान अपने लिए खरीदार भी खोजे, लेकिन जिन कंपनियों की यहां बात चल रही है, वे इस अवधि में ऐसा कुछ नहीं कर सकीं, जिससे लगे कि वे कर्ज चुकाने की स्थिति में आ गई हैं। आखिरी उपाय के तौर पर कर्जदाता बैंकों ने और इंडस्ट्री ने भी रिजर्व बैंक से मोहलत बढ़ाने की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अब आलम यह है कि 2000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का कर्ज लिए बैठी इन कंपनियों की सूची नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास भेजी जाएगी, जहां इनके खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इन कंपनियों पर कुल 3 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है। समझा जा सकता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था के लिए यह कितना बड़ा संकट है। ये सभी देश की बड़ी कंपनियां हैं। इनमें कितने लोग काम करते हैं और एक बार दिवालियेपन की प्रक्रिया में जाने के बाद इनका नियमित संचालन किस तरह प्रभावित होगा, इन कर्मचारियों की रोजी-रोटी का क्या होगा, इनसे जुड़े परिवारों का भविष्य क्या होगा, ऐसे तमाम जरूरी सवालों का जवाब देने की स्थिति में फिलहाल कोई नहीं है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि ये कंपनियां 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज वाली हैं। 1000 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों की बारी इसके बाद आनी है। इन कंपनियों में उत्पादन बाधित होने से बाजार पर और इनकी सहायक कंपनियों पर पड़ने वाले प्रभावों और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों को फिलहाल छोड़ दें तो भी यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि क्या यह प्रक्रिया बैंकों को उनका पैसा वापस लौटाने की गारंटी दे पाएगी। अगर 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर्ज वाली 12 कंपनियों के साथ जुड़े अनुभव पर गौर करें तो जवाब ना में ही मिलता है। इनमें से 11 कंपनियां एनसीएलटी की अलग-अलग बेंचों के जरिए समाधान की अलग-अलग अवस्थाओं में हैं और बैंकों को उनसे अपने पूरे कर्ज की आधी से कुछ ज्यादा रकम ही वापस मिलने की उम्मीद है। जून के अंत तक इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आईबीसी) के तहत जो 32 मामले सुलझाए जा सके थे, उनमें भी रिकवरी कुल दावे की करीब 55 फीसदी ही रही। ऐसे में सवाल यह बनता है कि आईबीसी की यह प्रक्रिया क्या सचमुच हमारी बैंकिंग व्यवस्था की बीमारी दूर कर सकती है? अगर नहीं, तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वसूली में सख्ती के नाम पर अर्थव्यवस्था को और ज्यादा झटके देने के बजाय हम अपना ध्यान बीमारी का कोई बेहतर इलाज खोजने पर केंद्रित करें?

पहली बार 70.52 के स्तर पर पहुंचा

डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ धड़ाम

नई दिल्ली। डॉलर के मुकाबले रुपये में जारी गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को कारोबार के दौरान रुपय फिर धड़ाम हो गया और यह ऐतिहासिक गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। बुधवार को रुपया 42 पैसे गिरकर 70.52 के स्तर पर पहुंच गया है। यह पहली बार है, जब रुपया एक डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर हुआ है। आयातकों की तरफ से महीने के आखिर में यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपया धड़ाम हो गया है। इससे पहले बुधवार की सुबह भी रुपये ने गिरावट के साथ शुरुआत की। एक डॉलर के मुकाबले रुपया 22 पैसे गिरकर खुला। आयातकों की तरफ से डॉलर की मांग बढ़ने का असर रुपये पर देखने को मिला। मंगलवार की बात करें तो रुपये ने इस दिन मजबूत शुरुआत की. बंद होने के दौरान भी यह 6 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ। मंगलवार को रुपया एक डॉलर के मुकाबले 70.16 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। मंगलवार को जिस यूएस-मेक्सिको डील के चलते वैश्विक बाजार में तेजी आई थी। उस डील को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत होते डॉलर और तुर्की में जारी आर्थिक संकट के चलते बन रहे समीकरणों ने रुपये को कमजोर करने का काम किया है। रुपये के कमजोर होने का असर कहीं न कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पहले कच्चे तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में रुपये में गिरावट की वजह से तेल कंपनियों की लागत भी बढ़ रही है। इसका सीधा असर तेल कंपनियों के खर्च बढ़ने के तौर पर सामने आ रहा है। इसकी वजह से लगातार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी का सिलसिला जारी है।

जन-धन के बाद गोल्ड सेविंग अकाउंट

नई दिल्ली। जन-धन अकाउंट के बाद सरकार अब एक नया अकाउंट लाने की तैयारी में है। इस अकाउंट का नाम होगा गोल्ड सेविंग अकाउंट। यह अकाउंट भी आम अकाउंट की तरह बैंकों की ब्रांच में खुलेगा। कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकेगा। बता दें कि गोल्ड सेविंग अकाउंट की खासियत होगी कि आप बैंक में जाकर पैसे जमा करेंगे। लेकिन आपके पासबुक पर राशि की जगह सोने की मात्रा चढ़ेगी। इसके बाद ग्राहकों को जरूरत के समय गोल्ड सेविंग अकाउंट से रकम या सोना दोनों ही निकालने की सुविधा मिलेगी। बता दें कि आम सेविंग एकाउंट की तरह गोल्ड सेविंग एकाउंट पर ब्याज भी मिलेंगे।

तेल की बढ़ती कीमतों के कारण 3.3 फीसद के लक्ष्य से पार जा सकता है भारत का राजकोषीय घाटाः मूडीज

नई दिल्ली एजेंसी

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का राजकोषीय घाटा 3.3 फीसद के लक्ष्य को पार कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल की लगातार बढ़ रही कीमतें अल्प अवधि में वित्तीय दबाव उत्पन्न करेंगी। अमेरिकी एजेंसी के मुताबिक, चालू खाता घाटा (सीएडी) जो कि विदेशी करेंसी के इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच का अंतर होता है, वो और चौड़ा होगा, लेकिन भारत की बाहरी स्थिति को खतरे में नहीं डालेगा और पांच साल पहले की तुलना में यह अंतराल काफी कम रहेगा। मूडीज ने कहा, 'तेल की

ऊंची कीमतें अल्प अवधि में वित्तीय दबाव उत्पन्न करेंगी। इसके बाद वस्तुओं एवं सेवाओं कर में कटौती और कुछ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अपेक्षाकृत उच्च वृद्धि भी असर डालेगी।'

सरकार ने मार्च 2019 तक चलने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का बजटीय लक्ष्य जीडीपी के अनुपात में 3.3 फीसद रखा है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान राजकोषीय घाटा 68.7 फीसद तक पहुंच गया है। इसके तेल की ऊंची कीमतों और मजबूत गैर-तेल आयात मांग से प्रेरित होने पर भी मूडीज की उम्मीद है कि मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 फीसद तक बढ़ जाएगा। यह साल 2018 में 1.5 फीसद रहा है। मूडीज के वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एनालिस्ट जॉय रंकोथगे ने बताया कि तेल की ऊंची कीमतें और उच्च ब्याज दरें सरकार के बजट पर दबाव बनाएंगी।

देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी ONGC को बड़ा झटका

निजी कंपनी वेदांता को 55 में से मिले तेल-गैस के 41 ब्लॉक

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में खुले रूप से ब्लॉक नीलामी सिस्टम में निजी क्षेत्र की वेदांता लिमिटेड ने बाजी मार ली। अनिल अग्रवाल की वेदांता ने सरकारी तेल कंपनियों को पछाड़ते हुए सर्वाधिक 41 ब्लॉक हासिल किए। जबकि सरकारी क्षेत्र की ओएनजीसी ने अन्य सहयोगी कंपनियों के साथ मिलकर 37 ब्लॉक के लिए दावेदारी की थी। मगर जब 55 ब्लॉक का आवंटन हुआ तो महज 14 ब्लॉक से ही संतोष करना पड़ा। सरकारी कंपनियों में ऑयल इंडिया (ओआईएल) को 9 ब्लाक, आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) को केवल 2 ब्लॉक, गेल को एक, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि। की खोज एवं उत्पादन इकाई को एक और हिंदुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कंपनी (एचओईसी) को एक-एक ब्लाक मिले।

मुनाफ कमा रही ओनजीसी, फिर भी यह हाल

चौंकाने वाली बात यह है कि तेल और गैस के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ओएनजीसी लगातार मुनाफा कमा रही है। भले ही देश के 157 सार्वजनिक उपक्रम एक लाख करोड़ के घाटे में चल रहे हों, मगर ओएनजीसी जैसी तेल कंपनियां हमेशा सरकार के लिए फायदमेंद

साबित होतीं रहीं हैं। सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी को लाभ की बात करें तो जून में खत्म हुई तिमाही में 6,143।88 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने खुद अपने बयान में साल-दर-साल आधार पर 58।15 फीसदी का मुनाफा दर्ज होने की बात कही थी। ओएनजीसी ने कहा था कि उसने पिछले साल की समान तिमाही में 3,884।73 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। बावजूद इसके तेल एवं गैस ब्लॉक आवंटन में कंपनी के पिछड़ने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

यह पहला मौका था, जब देश में तेल और गैस के लिए खोजे गए ब्लॉक की खुली नीलामी हुई। दरअसल केंद्र सरकार ने अप्रैल में एक फैसला लिया था, जिसमें खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (OALP) के तहत तेल और गैस ब्लॉक की नीलामी के विजेताओं को ब्लॉक आवंटन की बात थी। ब्लॉक आवंटन पर फैसला लेने के लिए वित्त और पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिकृत किया गया था। नई नीति के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे तेल-गैस की कीमतों में होने वाली बढ़ोत्तरी और उत्पादन वृद्धि दोनों स्थिति में सरकार को उचित हिस्सेदारी मिलेगी। जबकि पुराना यानी उत्पादन साझेदारी ठेके के मॉडल को विवादास्पद बताया जाता रहा

आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान: NCAER

नयी दिल्ली। एजेंसी

आर्थिक शोध संस्थान एनसीएईआर ने चालू वित्त वर्ष के लिये देश की आ्रथक वृद्धि दर के अनुमान को 7.4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। संस्थान ने कृषि क्षेत्र में संतोषजनक स्तर तथा बाह्य क्षेत्र में सुधार का हवाला देते हुए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को यथावत रखा है।नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड एकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) की रिपोर्ट के अनुसार 2018-19 में वास्तविक कृषि सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) 4.6 प्रतिशत, वास्तविक उद्योग

जीवीए 5.1 प्रतिशत तथा वास्तविक सेवा जीवीए 8.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। एनसीएईआर की सालाना और तिमाही माडल अनुमान दोनों में जीवीए के सालाना आधार पर 7 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। संस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में ताजा तिमाही समीक्षा में कहा गया है, ''वित्त वर्ष 2018-19 में बाजार मूल्य पर जीडीपी 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह मई 2015 में जताये गये अनुमान के बराबर है।'' डालर के रूप में निर्यात और आयात में वृद्धि दर क्रमशः 11.9 प्रतिशत तथा 15.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। चालू खाते का घाटा तथा केंद्रीय राजकोषीय घाटा क्रमशः 2 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।शोध संस्थान के अनुसार बारिश और कीमत दोनों की प्रवृत्ति से पूरे साल के लिये कृषि क्षेत्र परिदृश्य के संतोषजनक स्तर पर होने का पता चलता है। एनसीएआईआर ने कहा कि 2018-19 में बाह्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। वित्त वर्ष 2017-18 में निर्यात और आयात में सालाना आधार पर क्रमशः 9.9 प्रतिशत तथा 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

गेल का विभाजन नहीं होगा, पेट्रो-रसायन कारोबार बेचा जा सकता है: प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गेल के गैस परिवहन और विपणन कारोबार के अलग करने की बात से इनकार किया। हालांकि उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी को अपने गैर-प्रमुख पेट्रो रसायन कारोबार को अच्छे मूल्य पर बेचना चाहिए। एक ही इकाई के दोनों कारोबार से जुड़े होने से हितों के टकराव के मसले के समाधान के लिये गेल खातों को अलग करेगी और बाहरी इकाइयों के लिये अपने व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराएगी। प्रधान ने कहा, ''गेल के निदेशक मंडल ने मुद्दे पर विचार किया और कहा है कि वह दोनों कारोबार गैस परिवहन तथा विपणन का स्वतंत्र तथा स्वायत्त तरीके से परिचालन करेगी। कंपनी की आनलाइन पोर्टल की शुरूआत के मौके पर उन्होंने यह बात कही। इस पोर्टल के जरिये प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये गेल के पाइपलाइन नेटवर्क के उपयोग को लेकर विपणन इकाइयां तथा ग्राहक बुकिंग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गेल का विभाजन सरकार के एजेंडे में नहीं है। उनका मंत्रालय कंपनी के परिचालन में दक्षता चाहती है। प्रधान ने कहा कि गेल का गठन पाइपलाइन के निर्माण के मकसद से किया गया था और तीन दशक में वह गैस की बड़ी विपणनकर्ता बन गयी है। प्राकृतिक गैस ग्राहकों तक पहुंचाने के लिये पाइपलाइन जरूरी है। फिलहाल पाइपलाइन का संकेन्द्रण देश के केवल पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में है। उन्होंने कहा कि गेल को पाइपलाइन बिछाने पर ध्यान देना चाहिए। यह स्वीकार्य नहीं है कि वे विपणन और पेट्रोरसायन के लिये पाइपलाइन का उपेक्षा करे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में प्रधान ने कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने इस मुद्दे पर विचार किया और दोनों कारोबार के लिये अलग बही-खाते पर सहमति जतायी। साथ ही तीसरे पक्ष को पारदर्शी आधार पर अपना पाइपलाइन नेटवर्क को देने पर राजी हुई है। उन्होंने कहा कि पेट्रोरसायन गैर-प्रमुख कारोबार है। गेल को जब भी बेहतर मूल्य मिले, पट्रोरसायन कारोबार से बहार होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि गेल को काम करना है और देश के हर कोने में गैस पहुंचाने की आकांक्षा को पूरा करना है। पेट्रोलियम मंत्रालय पिछले कुछ महीने से गेल के कारोबार को अलग करने पर विचार कर रहा है ताकि एक ही इकाई के दोनों काम से हितों के टकराव के मुद्दे का समाधान हो सके। वास्तव में कुछ कंपनियां यह आरोप लगा रही थी कि गेल अपने 11,000 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का उपयोग नहीं करने दे रही। गेल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बी सी त्रिपाठी ने कहा कि गेल ने 2004 में पाइपलाइन नेटवर्क को खोला था। उस समय चार कंपनियों ने इसकी बुकिंग की थी। आज 115 ग्राहक गेल पाइपलाइन का उपयोग कर रही हैं। उल्लेखनीय है मंत्रालय ने जनवरी में कहा था कि वह गेल को दो कंपनियों में विभाजित करने पर विचार कर रही है। एक इकाई पापइलाइन बिछाने का काम करेगी और दूसरा पेट्रोरसायन के काम को देखेगी। इसका मकसद दोनों परिचालन में पारदर्शिता लाना था।

पेट्रोल की कीमत बेस प्राइस से 39.65 रुपये प्रति लीटर ज्यादा!

नयी दिल्ली। एजेंसी

पहली बार पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि दिल्ली में उसकी रीटेल कीमत में टैक्स और डीलर कमीशन की लागत बेस प्राइस से ज़्यादा हो गई। इंडियन आयल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को पेट्रोल की बेस प्राइस 38.26 प्रति लीटर थी जबकि पेट्रोल की रिटेल कीमत 77.91 रुपये थी। यानी बेस प्राइस से 39.65 प्रति लीटर ज्यादा! ट्रांसपोर्टर एसके मित्तल दशकों से इस कारोबार से जुड़े हैं। लेकिन पिछले एक साल से तनाव में हैं क्योंकि डीज़ल लगातार महंगा होता जा रहा है। इस वजह से लागत काफी बढ़ गई है। जबकि ट्रांसपोर्ट के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष एसके मित्तल, 'डीजल की कीमतों में हर रोज़ बदलाव ट्रांसपोर्टरों के लिए स्लो पायज़न है...हमने वित्त मंत्री को बताया है कि अगर अगले 6 से 8 महीने डीज़ल की कीमतों में इसी तरह बढ़ोत्तरी होती रही तो ट्रांसपोर्टर 50 लाख नए ट्रकों और लाइट मोटर व्हीकल्स की ईएमआई नहीं दे पाएंगे। दरअसल एक साल पहले 28 अगस्त 2017 को दिल्ली में डीज़ल की कीमत 57.03 रुपये लीटर थी जो 28 अगस्त 2018 में बढ़कर 69.61 रुपये लीटर हो गई। इससे साफ है कि सिर्फ एक साल में डीज़ल 12.58 रुपये लीटर महंगा हो गया...यानी 22.03ङ्म की बढ़ोतरी। चिंता पेट्रोल के दामों को लेकर भी बढ़ती जा रही है. दिल्ली में सोमवार को पहली बार पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि उसकी रिटेल कीमत बेस प्राइस से ज़्यादा हो गई। इंडियन आयल के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 27 अगस्त को दिल्ली में पेट्रोल की बेस प्राइस 38.26 रुपये थी...जबकि उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 19.48 रुपये थी, ॅंऊ 16.56 रुपये था और डीलर का कमीशन 3.61 रुपये था. यानी टैक्स और डीलर कमीशन मिलाकर बेस प्राइस से ज़्यादा।

इंदौर से मनमाड के बीच नई रेलवे लाइन बिछने से घटेंगी दूरियां

नई दिल्ली। एजेंसी

इंदौर और मनमाड के बीच आठ हजार करोड़ रुपये की लागत से 362 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए मंगलवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे छह वर्ष में पूरा किया जाएगा। इस लाइन के बनने के बाद इंदौर से मुंबई के अलावा दिल्ली से मुंबई, बंगलूर और चेन्नई की दूरी भी कम हो जाएगी। साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के पिछड़े आदिवासी इलाकों का विकास होगा। अभी इंदौर से मुंबई जाने के लिए गुजरात होते हुए 815 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। इंदौर-मनमाड लाइन के बनने के बाद यह दूरी 171 किलोमीटर घट जाएगी। इस लाइन का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के उन प्रमुख केंद्रों से होकर गुजरती है, जिनमें इगतपुरी, नासिक, सिन्नार, पुणे, खेड़ के अलावा धुले और नरदाना शामिल हैं। चूंकि यात्री यातायात के अलावा माल यातायात में भी इस लाइन का उपयोग होगा, लिहाजा इससे पहले दस सालों में ही 15 हजार करोड़ रुपये का समग्र शुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त होने की आशा है। इससे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसे व्यापारिक केंद्रों के मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल और इंदौर तथा महाराष्ट्र के धुले और मुंबई जैसे व्यापारिक केंद्रों से सीधे जुड़ने से परिवहन लागत में कमी आएगी। इससे रोजगार सृजन के अलावा प्रदूषण और ईंधन की खपत कम करने में भी मदद मिलेगी। इस लाइन का निर्माण केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर कर रही। लेकिन मुख्य प्रमोटर जहाजरानी मंत्रालय है जो इंडियन पोर्ट रेल कारपोरेशन लि. (आइपीआरसीएल) तथा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के मार्फत 55 फीसद पूंजी लगाएगा। जबकि रेल मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारें 15-15 के हिसाब से प्रतिशत इक्विटी योगदान करेंगी। इसके लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा। करेगा। समझौते पर खुशी जाहिर करते हुए जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पहली रेलवे लाइन है जिसका जिम्मा जहाजरानी मंत्रालय ने लिया है। यह सिंगिल लाइन होगी, जिसे बाद में डबल किया जा सकेगा। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चार पुलों के निर्माण का टेंडर भी निकाला जा चुका है। इसके बनने पर दिल्ली से बंगलूर और चेन्नई की दूरी भी 200-250 किलोमीटर कम हो जाएगी। रेलमंत्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस की मौजूदगी में, उन्होंने कहा कि परियोजना की लागत 9000 करोड़ रुपये तक जा सकती है।

इंदौर से पहली अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान सेवा दिसंबर तक संभव

इंदौर। केंद्र सरकार ने स्थानीय देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का परिचालन शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। अब इसके लिए आवश्यक तैयारियां योजना के अनुसार चलीं , तो मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाने वाला यह शहर अंतरराष्ट्रीय यात्री विमानन सेवाओं के नेटवर्क से इस साल के अंत तक जुड़ जाएगा। स्थानीय हवाई अड्डे की निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया, 'हमें अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के परिचालन के लिये केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय की सहमति मिल गयी है।' उन्होंने बताया कि स्थानीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय यातायात शुरू करने की योजना के मद्देनजर नागर विमानन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को यहां आव्रजन (इमिग्रेशन) चेक पोस्ट स्थापित करने के लिये लिखा है। इसके साथ ही, वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि स्थानीय हवाई अड्डे को सीमा शुल्क (कस्टम) विभाग के अधिसूचित विमानपत्तन का दर्जा दिलाने के लिये जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जायें। सान्याल ने कहा कि जरूरी सरकारी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद स्थानीय हवाई अड्डे से पहली अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ान दिसंबर तक शुरू होने की उम्मीद है. उन्होंने विशिष्ट जानकारी दिये बगैर बताया कि जेट एयरवेज ने इंदौर से अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की दिशा में रुचि दिखायी है। हालांकि, इस सिलसिले में कम्पनी का 'ठोस प्रस्ताव' फिलहाल प्रतीक्षित है। सान्याल ने बताया कि फिलहाल स्थानीय हवाई अड्डे पर 44 घरेलू उड़ानें आ रही हैं और इतनी ही घरेलू उड़ानें जा रही हैं। एक जनवरी से 30 जून तक करीब 13 लाख यात्री इस हवाई अड्डे के जरिये सफर कर चुके हैं। अनुमान है कि दिसंबर में खत्म होने वाले मौजूदा कैलेंडर वर्ष में यात्रियों की यह तादाद 26 लाख का स्तर पार कर जायेगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल स्थानीय हवाई अड्डे पर 11 पार्किंग बे हैं। इस परिसर में वर्ष 2019 तक 15 नये पार्किंग बे बनाने की योजना पर काम पहले ही शुरू हो गया है। सान्याल ने यह भी बताया कि स्थानीय विमानपत्तन को देश के अन्य हवाई अड्डों की तरह 'शांत हवाई अड्डा' बनाने के लिये उड़ानों की आवा-जाही की उद्घोषणा बंद करने पर विचार किया जा रहा है। इस प्रणाली को बंद करने के बाद हवाई अड्डा परिसर में उड़ानों के आने-जाने के समय की जानकारी देने वाले डिस्प्ले सिस्टम को मजबूत किया जायेगा। इसके साथ ही, यात्रियों के लिये सहायता डेस्क स्थापित की जायेगी।

जनवरी-जुलाई के दौरान भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 5.4 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन चालू कैलेंडर साल के पहले 7 महीनों जनवरी-जुलाई के दौरान 5.4 प्रतिशत बढ़कर 6.18 करोड़ टन पर पहुंच गया। वर्ल्ड स्टील असोसिएशन (ऐं) ने यह जानकारी दी है। असोसिएशन ने बयान में कहा कि इससे पिछले साल की समान अवधि में कच्चे इस्पात का उत्पादन 5.86 करोड़ टन रहा था। जुलाई में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 8.4 प्रतिशत बढ़कर 90 लाख टन रहा। जुलाई, 2017 में यह 83 लाख टन रहा था। जुलाई के दौरान दुनिया के 64 देशों में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन 5.8 प्रतिशत बढ़कर 15.46 करोड़ टन रहा। चीन का उत्पादन जुलाई में 7.2 प्रतिशत बढ़कर 8.12 करोड़ टन रहा। वहीं जापान का उत्पादन जुलाई में 2 प्रतिशत घटकर 84 लाख टन पर आ गया। सरकार ने इससे पहले कहा था कि भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन इस साल के अंत तक 38 प्रतिशत बढ़कर 14 करोड़ टन पर पहुंच जाएगा। देश का कच्चे इस्पात का उत्पादन 2017 में 10.14 करोड़ टन रहा था।

महंगाई भत्ते में 2% के अतिरिक्त इजाफे को कैबिनेट ने दी मंजूरी

एक करोड़ कर्मचारियों एवं पेशनर को होगा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय कैबिनेट ने आज महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में अतिरिक्त 2 फीसद की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के इस फैसले से करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेशनरों को फायदा होगा। यह जानकारी एक आधिकारिक रिलीज के जरिए सामने आई है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 9 फीसद डीए मिलेगा और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2018 से लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। डीए और डीआर दोनों के कारण वित्त वर्ष 2018-19 (जुलाई 2018 से फरवरी 2019 तक 8 महीने) में सरकारी राजकोष पर पड़ने वाला बोझ प्रतिवर्ष 6,112.20 करोड़ रुपये और 4,074.80 करोड़ रुपये का होगा।

इस फैसले में कहा गया, 'केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत देने के लिए अतिरिक्त किश्त को मंजूरी दे दी है। यह जुलाई 2018 के लागू होगी। इसमें 2 फीसद का इजाफा होगा जो कि वर्तमान में बेसिक सैलरी का 7 फीसद है।' कैबिनेट के इस फैसले से 48.41 केंद्रीय कर्मचारियों और 62.03 लाख पेंशनरों को फायदा होगा।

कैसे होती है डीए की गणना?

महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना कर्मचारी की बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के बाद इसे 5 फीसद से बढ़ाकर 7 फीसद कर दिया गया था। यह बढ़ोतरी जनवरी 2018 से लागू थी। अब जुलाई महीने से कर्मचारियों को 9 फीसद डीए मिलेगा।

सरकार आखिर क्यों देती है महंगाई भत्ता?

केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए महंगाई भत्ता देती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी सरकारों की ओर से अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है।

बड़े संकेत जो बताते हैं कि भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत की अर्थव्यवस्था में ट्रेड वार का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। वहीं इसी बीच उसे अपने घरेलू उपभोग पर भरोसा है ताकि वो इस साल भी सबसे तेज अर्थव्यवस्था की राह पर बना रहे। बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद बैंक कर्ज की मांग जुलाई तिमाही में ठोस रही है। विदेशी निवेश की रफ्तार सुस्त रही है जिसने भुगतान संतुलन के जोखिम को रेखांकित किया है। अन्य जोखिमों की बात करें तो उनमें तेल की बढ़ती कीमतें, सख्त होती वैश्विक परिस्थितियां और कर संग्रह में आ रही गिरावट प्रमुख हैं जो कि बजट लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना को कम कर रहे हैं। इन सबों के बावजूद समझिए कैसे भारत सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

बिजनेस गतिविधियां

भारत का मुख्य सर्विस इंडेक्स जुलाई महीने में 21 महीनों के उच्चतम स्तर पर रहा, ताजा पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने यही स्थिति बयां की थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में लगातार इजाफा देखने को मिला है, हालांकि सुस्त रफ्तार से। इन दोनों ने ही कंपोजिट इंडेक्स को अक्टूबर 2016 के बाद के उच्चतम स्तर पर ला दिया है। नए ऑर्डर्स में इजाफे से आशावाद का जन्म होता है क्योंकि इससे व्यवसायों को और अधिक उत्पादन करने का विश्वास मिलता है।

निर्यात

बीते साल के मुकाबले जुलाई महीने में निर्यात 14.3 फीसद बढ़ा है। हालांकि यह इसके पिछले महीने के मुकाबले 18 फीसद कम रहा। अर्थशास्त्री और नीत निर्माता आशान्वित हैं कि रुपये में आई हालिया गिरावट टेक्सटाइल सेक्टर को रिकवरी में मदद करेगी। उपभोक्ता गतिविधियां: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई महीने में इंडस्ट्री ने ज्यादा व्हीकल्स का प्रोडक्शन किया। इसमें कमर्शियल व्हीकल और टू-व्हीलर में तेज इजाफा देखने को मिला। हालिया बिक्री आंकड़ों में 8 फीसद की तेजी देखने को मिली है।

एथनॉल क्षमता स्थापित करने के लिय सरकार को मिले 150 प्रस्ताव

नयी दिल्ली। सरकार को एथनॉल क्षमता के विस्तार तथा इकाई लगाने के लिये हाल में शुरू योजना के तहत करीब 150 प्रस्ताव मिले हैं। इसमें बजाज हिंदुस्तान जैसी कंपनियों के प्रस्ताव शामिल हैं। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। सरकार ने जून में एथनॉल क्षमता सृजित करने के लिये मिलों को 4,440 करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज देने की घोषणा की। साथ ही एक साल की रोक के साथ 1,332 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता का भी वहन करने का वादा किया है। सरकार ने गन्ना किसानों के भारी बकाये के भुगतान के लिये कदम उठाये हैं, यह उसमें शामिल है। एक अधिकारी ने कहा, "चीनी मिलों ने एथनॉल क्षमता सृजित करने के लिये रूचि दिखायी है। हमें अबतक 150 प्रस्ताव मिले हैं। हम उसकी जांच कर रहे हैं।" ये प्रस्ताव देने वाले ज्यादातर मिल उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। प्रस्ताव में नई एथनॉल क्षमता के विस्तार के साथ उसकी स्थापना शामिल हैं। अधिकारी के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि मंत्रालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद वह बैंकों के लिये कर्ज देने को लेकर बाध्यकारी हो। उसने कहा, "एक बार हम प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं, वह वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के पास जाएगा। उस पर विचार करने के बाद उसे संबंधित नोडल बैंक को भेजा जाएगा। बैंक परियोजना रिपोर्ट, मिल का बही-खाता देखेगा और उसके बाद निर्णय करेगा।"फिलहाल बैंक चीनी क्षेत्र में जोखिम को देखते हुए चीनी मिलों को कर्ज देने को लेकर गंभीर नहीं है। हालांकि यह देखना होगा कि कितनी मिलें योजना के तहत सब्सिडी वाले ब्याज दर पर सस्ता कर्ज प्राप्त कर पाएंगी। गन्ने से निकाला जाने वाला एथनॉल का उपयोग पेट्रोल में मिलाने में किया जाएगा और इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल पाएगा। पेट्रोल में एथनॉल के मिश्रण से देश को आयात बिल में कमी लाने में मदद मिलेगी।

गोल्ड बोर्ड और बुलियन एक्सचेंज पर काम शुरू! सोने पर नीति आयोग की ये सिफारिशें हुई मंजूर

नई दिल्ली। एजेंसी

जानकारी के मुताबिक नीति आयोग की सिफारिशों के मुताबिक गोल्ड बोर्ड और बुलियन एक्सचेंज बनाने पर काम शुरू हो गया है। नीति आयोग ने गोल्ड पॉलिसी पर 84 सिफारिशें की थीं लेकिन सबसे अहम सिफारिश, ड्यूटी घटाने पर सहमति नहीं बनी है।

गोल्ड पर ड्यूटी घटाने पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है। अभी गोल्ड इंपोर्ट पर 10 फीसदी ड्यूटी है। गोल्ड पर जीएसटी घटाने पर भी वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है। फिलहाल अभी गोल्ड पर 3 फीसदी जीएसटी लगता है। सरकार की ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स पर ड्यूटी का बोझ हटाने की कोशिश है। जिसके लिए ज्वैलरी एक्सपोर्ट पर जीएसटी की बैंक गारंटी लेने पर विचार किया जा रहा है। गोल्ड बोर्ड ऑफ इंडिया की सिफारिश भी मंजूर कर ली गई है। इसके अलावा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में बदलाव और इंडियन गोल्ड क्वॉइन लॉन्च करने, बुलियन एक्सचेंज पर काम शुरू करने एमईआईएस स्कीम में ज्वेलरी को शामिल करने, ज्वैलरी को मेक इन इंडिया में प्राथमिकता और अलग-अलग चरणों में हॉलमार्किंग जरूरी बनाने की सिफारिश मंजूर कर ली गई है।

एक लीटर पेट्रोल की कीमत 85.60 रुपये

जानिए क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

नई दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 78.18 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। कोलकाता की बात करें तो यहां पर आपको 81.11 रुपये प्रति लीटर देने पड़ रहे हैं। चेन्नई में एक लीटर पेट्रोल 80.59 रुपये का मिल रहा है। वहीं, डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी जारी है। बुधवार को डीजल मुंबई में 74.05 प्रति लीटर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 69.75 के स्तर पर पहुंच चुकी है। कोलकाता की बात करें तो यहां पर आपको इसके लिए 72.60 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। चेन्नई में इसके लिए आपको 73.84 रुपये प्रति लीटर देने होंगे। क्यों बढ़ रही पेट्रोल और डीजल कीमत- पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जारी लगातार गिरावट जारी है। कच्चा तेल की बढ़ती कीमतें जिम्मेदार हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये में बढ़ोत्तरी के लिए गिरता रुपया और कच्चे तेल लागत में भी इजाफा हो रहा है। इसके चलते तेल कंपनियों की कीमतों में बढ़ोत्तरी का सिलसिला भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ और डीजल की जारी हो गया है।

डूबे कर्ज की समस्या से निजात नहीं, 2018-19 में और बढ़ेगा NPA: रिजर्व बैंक

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि बैंकों को अभी गैर NPA एनपीए की समस्या से निजात नहीं मिलने वाली। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष में बैंकों का डूबा कर्ज और बढ़ेगा। रिजर्व बैंक की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग प्रणाली में मार्च, 2018 के अंत तक कुल ऋँ और पुनर्गठित कर्ज कुल ऋण के 12.1 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीए पर प्रावधान बढ़ने और बॉन्ड पर प्राप्ति बढ़ने की वजह से मार्क टु मार्केट (एमटीएम) ट्रेजरी नुकसान जैसे सामूहिक प्रभाव से बैंकों का मुनाफे पर असर हुआ है और शुद्ध रूप से उनको घाटा उठाना पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एएँ) का कुल सकल एनपीए 31 मार्च, 2018 तक बढ़कर 10,35,528 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 31 मार्च, 2015 को 3,23,464 करोड़ रुपये था। बता दें कि मंगलवार को वित्तीय मामलों से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय इस बारे में पिक्चर साफ करने के लिए एक कमिटी बनाए कि अभी बैड लोन और एनपीए से जूझ रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर किसका रेगुलेटरी अधिकार है क्योंकि आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अधिकारी 'जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल रहे हैं।'

भारतीय स्टेट बैंक ने बदले 1,300 शाखाओं के नाम, IFSC कोड

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने देशभर में करीब 1,300 शाखाओं के नाम और आईएफएससी कोड में परिवर्तन किया है। बैंक ने ऐसा उसके छह सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का उसमें विलय होने के बाद किया है। बैंक ने ही इन शाखाओं के नए नाम और नए आईएफएससी कोड की सूची जारी की है। कुल 1,295 शाखाओं के नाम में यह परिवर्तन किया गया है। बता दें कि एसबीआई के छह सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का उसमें विलय एक अप्रैल 2017 से प्रभावी है। बैंक ने जो सूची जारी की है उनमें इन शाखाओं के पुराने नाम और आईएफएससी कोड का भी जिक्र किया गया है। किस बैंक का नया कोड क्या है उसे एसबीआई की वेबसाइट पर देका जा सकता है। एसबीआई जमा राशि के मामले में भारत का सबसे बड़ा भारतीय बैंक है। इसकी देशभर में 22,428 ब्रांच हैं। पिछले साल अप्रैल में पांच सहयोगी बैंकों- स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और भारतीय महिला बैंक का भी एँ में विलय हो गया था।

ईरान ने भारत को तेल निर्यात जारी रखने के लिए किया ढुलाई बीमा सुरक्षा देने की शुरुआत

नई दिल्ली। ईरान ने भारत को कच्चा तेल निर्यात जारी रखने के लिए ढुलाई पर बीमा सुरक्षा तथा अपने जहाज मुहैया कराना शुरू किया है। इससे सीधे जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी हैष उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा आर्थिक प्रतिबंध पुन : लगाये जाने के बाद पश्चिमी देशों की बीमा कंपनियां पीछे हटने लगी हैं। ऐसे में उसने भारत को कच्चा तेल निर्यात करने के लिए अपने जहाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तथा ढुलाई के लिए बीमा सुरक्षा भी देने लगा है।

उन्होंने कहा कि ईरान के तेल की ढुलाई के लिए जारी हालिया निविदा में कई ढुलाई कंपनियों के भाग नहीं लेने के कारण उसने भारत को तेल भेजने में अपने जहाजों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इससे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड (एचपीसीएल) को बीमा सुरक्षा संबंधी दिक्कतों के कारण ईरान के तेल की खेप की खरीद रद्द करनी पड़ी थी। सूत्रों ने कहा कि यह एक तात्कालिक समस्या है और 2012 में भी ईरान पर प्रतिबंध लगाये जाने के बाद शुरुआती दौर में ऐसी दिक्कतें आयी थीं। भारत ईरान के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

पूर्ण आनंद के प्रतीक हैं श्रीकृष्ण

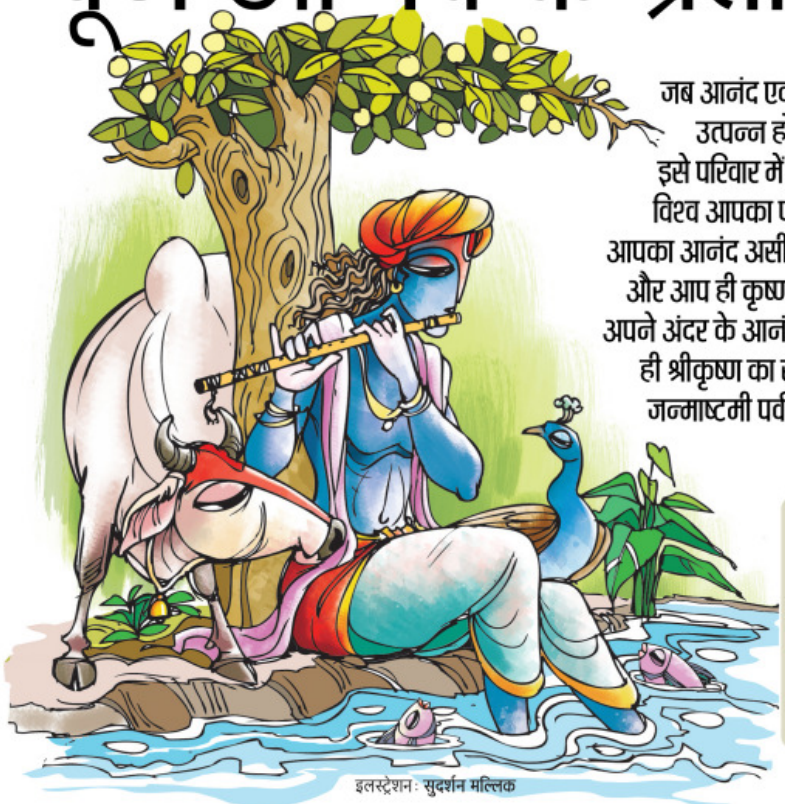

इलस्ट्रेशन: सुदर्शन मल्लिक

जब आनंद एक बार आप में उत्पन्न होता है तो आप इसे परिवार में बांटते हैं। पूरा विश्व आपका परिवार है। तब आपका आनंद असीम हो जाता है और आप ही कृष्ण बन जाते हैं। अपने अंदर के आनंद को जगाना ही श्रीकृष्ण का संदेश है। यही जन्माष्टमी पर्व का संदेश है।

जन्माष्टमी पर विशेष

श्री श्री रविशंकर

जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव है। कृष्ण को जगद्गुरु कहा जाता है। कृष्ण एक पूर्ण आनंद की प्रतिमूर्ति हैं। इसीलिए उनके साथ कुछ शरारतों की घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। शरारत का उदय ही प्रसन्नता से होता है। लोग उनकी शिकायतें करने आते, लेकिन उन्हें देखते ही सभी शिकायतें और गुस्सा गायब हो जाते। शुद्ध प्रसन्नता और आनंद के समक्ष कोई शिकायत और गुस्सा नहीं ठहरता है। आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो तो आप खुल कर मुस्करा सकते हैं, जब बुरे दिनों में आप मुस्करा पाएं तो ही आपने जीवन में कुछ उपलब्धि प्राप्त की है। कृष्ण में यही गुण था। उनकी मुस्कान सबको मोहित करती थी।

उनका मटका तोड़ना, उसमें से मक्खन निकलना..., इस कहानी का गहरा अर्थ है। यहां पर मटके का तात्पर्य है शरीर और मक्खन का अर्थ है सार। जब हम शरीर की सीमा से अपने आप को बाहर पाते हैं तो हमें जीवन के सार का पता चलता है। हमारे असीम चैतन्य को खिलने से कौन रोकता है, 'मैं एक शरीर हूं'- यह विचार ही एकमात्र बंधन है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ तोड़ कर हम हंसते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रेम में हों तो प्रेम से खिल उठते हैं। हमारा सार प्रेम के रूप में बाहर निकलता है।

कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है; एकमात्र वही चोर हैं, जिनका पूर्ण सम्मान हुआ है। वह माखन चोर हैं, क्योंकि वह उनका मन भी चुरा लेते हैं, जिन्होंने प्रेम को पा लिया है, जिनकी चेतना पूर्ण खिल चुकी है। हम उन्हें चितचोर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है मन को चुराना। उनका जन्म देवकी यानी शरीर और वासुदेव यानी श्वास के यहां पर हुआ। जब प्राण का शरीर के साथ समागम होता है तो आनंद का जन्म होता है। इसीलिए कृष्ण को नंदलाल कहा जाता है, क्योंकि नंद या आनंद का अर्थ है प्रसन्नता।

जब कृष्ण का जन्म हुआ था सभी पहरेदार सो गए थे। ये पहरेदार और कोई नहीं, हमारी पांचों इंद्रियों को कहा गया है, जो आंतरिक प्रेम और आनंद को अनुभव नहीं होने देते। कृष्ण का मामा कंस और कोई नहीं, हमारा अहंकार है, जिसने हमारे वासुदेव और देवकी को बंधक बना रखा है, जिसके कारण हमारे प्राण और शरीर कैद में हैं। अहंकार सदैव प्रसन्नता से दूर होता है, इसीलिए यह प्रसन्नता का वध करने के प्रयास में लगा रहता है।

बच्चे सदैव प्रसन्नता से भरे होते हैं, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं होता। जिस क्षण हम में पृथकता या अलग होने की प्रवृत्ति जन्म लेती है, आनंद समाप्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण को आधी रात को लेकर जाना पड़ा, क्योंकि उस आनंद को कंस समाप्त नहीं कर सकता था। कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव उनको यमुना नदी, जो प्रेम का सूचक है, के पार लेकर गए। पूरे साहस से भरे वासुदेव बाढ़ से उफनती यमुना नदी को पार कर रहे थे और जैसे ही वे डूबने को हुए, तभी कृष्ण ने अपना पैर टोकरी से बाहर निकाल कर यमुना के उफान को रोका। इसका अर्थ है कि जब भी विपत्ति नाक तक आती है तो ईश्वरीय सहायता सदैव वहां पर रहती है। इस से ऊपर कठिनाई आ नहीं सकती, क्योंकि यह इसके बाद ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है।

कृष्ण ने नियमों को माना, लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जहां कृष्ण ने नियम को अनदेखा किया। ईश्वर रचना के हर हिस्से में मौजूद है। दिव्यता शर्तरहित है, लेकिन हमारी धारणाएं हमें दिव्य प्रेम और मासूमियत से दूर ले जाती हैं। इसीलिए आलोचनात्मक नहीं बनें। जो जैसा है, उसे स्वीकार करें।

एक बार कृष्ण को बुरी तरह प्रभावित किया गया। एक मणि के चोरी होने का आरोप उन पर लगाया गया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया कि मणि उनके पास नहीं है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। यहां तक कि रुक्मिणी, सत्यभामा व बलराम ने भी नहीं किया। यह देख कर कृष्ण अप्रसन्न हो गए। तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने बताया कि यह आपका मन है, जो उत्तेजित हुआ है, आप स्वयं नहीं। स्व तो सभी प्रकार के मन से परे होता है। मन की खिन्नता को देखने से हम उस खिन्नता से बाहर चले जाते हैं। इस प्रकार जब भी आप खिन्न हों और यदि आप ये सोच रहे हों कि ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था, तो उसे तुरंत समर्पण कर दें। यह मन ही है, जो खिन्न होता है, आप स्वयं कभी खिन्न नहीं होते।

कृष्ण एक पांव को धरती पर पूरी तरह जमा कर और दूसरे पांव को धरती पर हल्के से रख कर खड़े होते हैं। इसका तात्पर्य है कि जीवन को एक पूरे संतुलन के साथ जीना चाहिए। जीने की कला का अर्थ है अध्यात्म और भौतिकता में संतुलन कैसे बनाया जाए।

श्रीकृष्ण महिमा

जीवन के हर रूप में मोहते हैं कृष्ण

विभिन्न आलौकिक कृत्यों के बीच श्रीकृष्ण जीवन में माधुर्य का संदेश देना नहीं भूलते। वह विभिन्न प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हैं, मनमोहक बांसुरी वादन करते हैं तथा रास जैसी मोहक नृत्य विधा का सृजन करते हुए समस्त बृज प्रांत को महारास के रस में डुबो देते हैं, जिसमें सम्मिलित होने का लोभ संवरण स्वयं देवाधिदेव महादेव भी नहीं कर पाते और स्त्री वेश धारण कर इस महारास में सम्मिलित होते हैं।

बृज के समस्त गोप-गोपियां श्रीकृष्ण के साथ भावनात्मक तथा आध्यात्मिक रूप से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि श्रीकृष्ण के बिना वे अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक आते-आते श्रीकृष्ण अपने 'कर्मन्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' के विचार को मूर्त रूप देते हैं। जब कर्तव्यपालन हेतु अपना गांव छोड़ कर जाना पड़ता है तो सभी ग्रामवासी व्याकुल होकर उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु श्रीकृष्ण भावनाओं के ऊपर कर्तव्य को प्रधानता देते हुए मथुरा को प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्हें अपने अत्याचारी मामा कंस का वध करना है। इसके बाद पूरे जीवनकाल में वह कभी भी वापस गोकुल या बृज में नहीं जाते।

भगवान के विभिन्न अवतारों में से श्रीकृष्ण इसलिए सबसे अलग दिखाई पड़ते हैं। श्रीकृष्ण अपने प्राकट्य के साथ ही अपने परम वैभवशाली, परब्रह्म स्वरूप का आभास देना प्रारम्भ कर देते हैं, और बाल्यावस्था तक आते-आते सभी को यह विश्वास हो जाता है कि वे दैवीय शक्ति से सम्पन्न हैं।

श्रीकृष्ण 'अहिंसा परमो धर्मः' का उपदेश अर्जुन को देते हैं, तो 'धर्महिंसा तथैव च' का उद्घोष करने से भी नहीं चूकते। जो कृष्ण आवश्यकता पड़ने पर कालयवन से भागते हुए स्वयं रणछोड़ के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, वह ही समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर युद्ध से विरत होते अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं।

श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि नवधा भक्ति के अनुसार हर प्रवृत्ति का भक्त अपनी भक्ति के अनुसार उनकी छवि गढ़ कर भक्ति कर सकता है। दैत्यों का वध करते कृष्ण, कहीं वंशी बजाते एवं रास रचाते कृष्ण, कहीं गीता उपदेश करते योगेश्वर कृष्ण, कभी द्रौपदी तथा कुब्जा के दुख को दूर करते कृष्ण। जीवन के हर क्षेत्र तथा हर रूप में श्रीकृष्ण पूर्ण दिखाई देते हैं, शायद इसीलिए भक्तों ने इन्हें पूर्णावतार कहा।

दिनेश चंद्र पाठक

आस्था स्थली: घनश्याम मंदिर, जोधपुर, राजस्थान

जहां राजा रूप में पूजे जाते हैं कान्हा

राजस्थान के जोधपुर शहर की हृदय स्थली में स्थित है घनश्याम जी का यह मंदिर। यहां चांदी की पालकी पर कान्हा जी विराजमान हैं। मंदिर में कान्हा जी की मूर्ति का शृंगार अद्भुत है। हर रोज प्रतिमा का फूलों से नए कलेवर में शृंगार किया जाता है। मंदिर के गर्भ गृह पर लिखा है- जय श्याम री सा... मंदिर में कान्हा जी की पूजा घनश्याम राजा के तौर पर होती है। इस विशाल मंदिर का निर्माण मारवाड़ शासक महाराजा अजीत सिंह ने 1685 में करवाया था। वह बड़े ही कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी राजा थे। उनका शासन काल 1678 से 1724 तक था।

दर्शन का समय
मंदिर प्रातः 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। बीच में दोपहर 12.30 से शाम 5 बजे तक बंद रहता है।

घनश्याम मंदिर के प्रांगण में विष्णुप्रिया तुलसी विराजती हैं, मंदिर की दीवारों पर धार्मिक कथाओं को चित्रों में दिखाया गया है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर, मंदिर की छत पर सुंदर पेंटिंग बनी हैं। बाहर से मंदिर सफेद रंग का है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाद विशाल आंगन है। मुख्य द्वार का नाम अजीत द्वार है। इस द्वार का निर्माण 1718 में हुआ था। बाद में 1964 में इसे नया रूप दिया गया। मंदिर में सेवा और पूजा वैष्णव पद्धति से की जाती है।

घनश्याम मंदिर की होली भी काफी प्रसिद्ध है। भक्त लोग कान्हा जी के सामने रंग भरी होली खेलते हैं। मंदिर में होली का त्योहार डेढ़ महीने तक चलता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो कोई सच्चे दिल से मांगता है, श्री श्याम जी उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए रोज हजारों की संख्या में यहां श्रद्धालु आते हैं और यहां दर्शन कर अपना जीवन धन्य बनाते हैं। पूरा मंदिर सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव यहां बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है।

कैसे पहुंचें : घनश्याम मंदिर जोधपुर के महावीर पोल इलाके में है। ये मंदिर जोधपुर शहर के एकदम बीच में बना हुआ है। यह इलाका जुनी मंडी के नाम से जाना जाता है। यह रेलवे स्टेशन से पांच किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के बगल में यहां टैक्सी स्टैंड है। जोधपुर देश के विभिन्न स्थानों से रेलमार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है। सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से भी जोधपुर पहुंचा जा सकता है।

माधवी रंजना

रॉयल एनफील्डः Classic 350 का ये स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च

नई दिल्ली।एजेंसी

रॉयल एनफील्ड Classic 350 सिग्नल्स एडिशन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इसकी कीमत 1.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, पुणे) रखी है। ये स्पेशल एडिशन बाइक इंडियन आर्म्ड फोर्सेज से इंस्पायर्ड है, जिसे इस मोटरसाइकल की स्टाइलिंग में देखा जा सकता है।

इस बाइक में खास अपडेट की बात करें तो नई Royal Enfield Classic 350 में अब डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) को शामिल किया गया है। Classic 350 सिग्नल्स एडिशन भारत में रॉयल एनफील्ड की अब ऐसी पहली बाइक बन गई है जिसमें डुअल-चैनल ABS दिया गया है। इस बाइक को डीलरशिप पर एक्सक्लूसिव रूप से बेचा जाएगा. इसकी बिक्री ऑनलाइन नहीं की जाएगी. इस बाइक के लिए बुकिंग शुरू कर दी गई है।

रॉयल एनफील्ड Classic 350 सिग्नल्स एडिशन दो कलर ऑप्शन- एयरबोर्न ब्लू और स्टोर्म राइडर सैंड में उपलब्ध होगी। ये नया मॉडल इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को समर्पित किया गया है। इस नई बाइक में स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही इंजन दिया गया है। यानी इस मोटरसाइकल में 346cc, एयर-कूल्ड इंजन दिया गया है। ये इंजन 19.8 bhp का पावर और 28 Nm का पिक टॉर्क जेनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इस इंजन को 5-स्पीड गियर बॉक्स से जोड़ा गया है.

ब्रेकिंग के लिए इस बाइक के फ्रंट और रियर दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिया गया है। साथ ही इस बाइक में मौजूद डुअल-चैनल ABS सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। इस बाइक के टैंक में मेटल वाला रॉयल एनफील्ड का बैज भी दिया गया है, जिसकी फिनिशिंग गोल्ड और ग्रीन में है। साथ ही आपको बता दें न्यू एडिशन बाइक को बिना रियर सीट के ही डिस्प्ले किया गया है। हालांकि कंपनी का कहना है कि मोटरसाइकल के साथ इसे उपलब्ध कराया जाएगा।

बारिश में तेजी के साथ बढ़ी फसलों की बुआई

नई दिल्ली। एजेंसी

देश में 94 पर्सेंट कृषि क्षेत्र में खरीफ की फसलों की बुआई हो गई है। सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर पश्चिमी, मध्य और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह में बारिश में तेजी के साथ बुआई बढ़ी है। हालांकि, बुआई अभी भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कुछ कम है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा से पता चलता है कि इस सीजन में अभी तक 995.62 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.28 पर्सेंट कम है। मोटे अनाज, कपास, धान और दालों के रकबे में कमी आई है, जबकि तिलहन और गन्ने का रकबा बढ़ा है। मॉनसून के डेटा के अनुसार, 1 जून से बारिश सामान्य से 7 पर्सेंट कम थी। हालांकि, देश के 91 बड़े जलाशयों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 28 पर्सेंट अधिक पानी थी। इससे मॉनसून के समाप्त होने के बाद भी फसलों के लिए पानी की उपलब्धता अच्छी बनी रहने का संकेत मिल रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि देश के जिन क्षेत्रों में किसानों को अधिक या कम बारिश के कारण फसल की दोबारा बुआई करनी पड़ती है, वहां किसान अब मोटे अनाज और दालों जैसी कम अवधि की फसलों की बुआई करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और कर्नाटक में सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में जिन किसानों ने धान की बुआई की तैयारी की थी वे अब बुआई करेंगे। अभी तक 356.83 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है, यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.75 पर्सेंट कम है।

दालों का बुआई क्षेत्र 2.27 पर्सेंट घटकर 130.83 लाख हेक्टेयर है। हालांकि, अरहर जैसी कुछ दालों का रकबा बढ़ा है। मोटे अनाज का रकबा 4.48 पर्सेंट गिरकर 166.52 लाख हेक्टेयर है। गर्मी के महीनों में बुआई वाले बाजरे, रागी का रकबा गिरा है, जबकि ज्वार और मक्का के रकबे में कुछ वृद्धि हुई है। किसानों ने इस वर्ष तिलहन विशेषतौर पर सोयाबीन की बुआई अधिक की है। तिलहन का बुआई क्षेत्र 1.68 पर्सेंट बढ़कर 167 लाख हेक्टेयर की है। सोयाबीन का रकबा 6 पर्सेंट की वृद्धि के साथ 111.29 लाख हेक्टेयर है। हालांकि, मूंगफली का बुआई क्षेत्र 4 पर्सेंट गिरा है। सूरजमुखी और कैस्टर के रकबे में भी कमी आई है।

विदेश से आयी कुल राशि में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2016-17 में विदेश से देश आये कुल धन (रेमिटेंस) का करीब 60 प्रतिशत केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिस्से में आया हैं। रिजर्व बैंक के एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गयी है। रिजर्व बैंक के इनवार्ड रेमिटेंसेज सर्वे के अनुसार, इस दौरान देश आये कुल धन में 74.20 प्रतिशत निजी बैंकों के रास्ते आये. सार्वजनिक बैंकों की इनमें 17.30 प्रतिशत और विदेशी बैंकों की 8.50 प्रतिशत हिस्सेदारी रही। उसने कहा, ''केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में विदेश से आये कुल धन का 58.70 प्रतिशत आया। सर्वेक्षण के अनुसार विदेश से आये कुल धन का करीब 82 प्रतिशत आठ देशों संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, ब्रिटेन और मलेशिया से आये।

भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी रोकने में आगे है मॉरिशस: IFC

नई दिल्ली। एजेंसी

मॉरिशस आर्थिक विकास बोर्ड ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने में मारिशस अग्रणी रहा है और मॉरिशस के आईएफसी द्वारा कर प्रावधानों का अनुपालन करवाने की दिशा में उपाय किए गए हैं। मॉरीशस की संस्था की ओर से यह बयान हालिया मीडिया रिपोर्ट के सिलसिले में आया है। रिपोर्ट में मॉरिशस समेत 25 देशों को अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिन्हित किया गया है। मॉरीशस आर्थिक विकास बोर्ड के वित्तीय सेवा प्रमुख फराज रोजीद ने कहा, 'मॉरीशस के आईएफसी (इंटरनैशनल फाइनैंशल सेंटर) को अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने विश्वसनीय संगठन के तौर पर मान्यता प्रदान की है। आईएफसी ने धनशोधन और आंतकियों को धन मुहैया करवाने की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाए हैं। सूचनाओं के आदान-प्रदान में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय मानकों और नियमों के अनुसार विधिक एवं विनियामक उपायों को अपनाया है।' उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर चोरी और अन्य भ्रष्टाचारों के खिलाफ जंग में मॉरिशस हमेशा सबसे आगे रहा है। फराज के मुताबिक, कर मामलों में पारदर्शिता और सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) के वैश्विक मंच की ओर से अनुपालन के क्षेत्राधिकार के तौर पर आईएफसी की जो रेटिंग की गई है, वह सर्वाधिक है। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर 2017 में कर मामलों में असहयोग करनेवाले क्षेत्रों को लेकर यूरोपीय संघ की ओर से जो सूची प्रकाशित की गई थी उसमें मॉरिशस शामिल नहीं है।

घरेलू कपड़ा उद्योग में सुधार के संकेत : सीआईटीआई

नई दिल्ली। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सीआईटीआई) के अध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि देश के कपड़ा उद्योग का बुरा दौर समाप्त हो गया है और अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। संजय जैन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का वस्त्र एवं परिधान निर्यात सात फीसदी सालाना दर से बढ़ सकता है। उन्होंने बताया कि बीते महीने जुलाई में देश का कपड़ा निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 11 फीसदी बढ़ा है और कपड़े के सभी मदों के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई। संजय जैन ने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से उद्योग को सहारा मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान के विभिन्न मदों पर आयात कर बढ़ा कर घरेलू उद्योग को प्रोत्साहन दिया है और इससे आने वाले दिनों में कपड़े का आयात घटेगा जिससे घरेलू उद्योग को मदद मिलेगी. भारत ने जुलाई में 6,284 करोड़ रुपये का कॉटन यार्न, फेब्रिक, मेडअप और हैंडलूम उत्पादों का निर्यात किया जोकि पिछले साल के मुकाबले 23 फीसदी ज्यादा है।

ड्रोन्स को भारत में उड़ाने की मिली अनुमति

जानें नियम से लेकर हर छोटी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। एजेंसी

नागर विमानन महानिदेशालय अक्टूबर 2017 को भारत में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी बनाने के सम्बन्ध में सामने आया था। अब अगस्त 2018 में सरकार ने ड्रोन्स के कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। ड्रोन्स नियामक 1.0 आ गया है और ये नियम 1 दिसंबर 2018 से लागू होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय ने ड्रोन नियामक 2.0 पर भी काम करना शुरू कर दिया है। ड्रोन का परमिट नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद 7 कार्यकारी दिनों के अंदर दिया जाएगा। इसकी वैधता इश्यू होने की तारिख से 5 वर्षों की होगी। इसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। एक ड्रोन पायलट एक समय में एक से अधिक ड्रोन कंट्रोल नहीं कर सकेगा। सभी ड्रोन पायलट का इंश्योरेंस होना जरुरी है। एयरपोर्ट, तटीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लोकेशन्स, सभी राज्यों में स्थित सचिवालय आदि पर नही उडाया जा सकेगा। ड्रोन उड़ाने की योग्यता न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम से 10वीं पास, डीजीसीए से अप्रूव्ड संस्था से ट्रेनिंग ली हो। नियम तोड़ने पर आईपीसी की धारा 287, 336, 337, 338 के तहत जुर्माना व दंड मिलेगा। डीजीसीए यूआईएन और यूएओपी निलंबित व रद्द भी कर सकता है।

ड्रोन से सम्बंधित शिकायत किसी तरह की दुर्घटना की रिपोर्ट डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए अपने ड्रोन की डिटेल सहित तुरंत निदेशक, एयर सेफ्टी को देनी होगी। शिकायत सरकार के पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर कर सकेंगे। पुराने ड्रोन खरीदने-बेचने के लिए यूआईएन किसी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके लिए बेचने वाले को अपना यूआईएन रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा और खरीदने वाले को नए यूआईएन के लिए आवेदन करना होगा। पिज्जा डिलीवरी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल को अभी अनुमति नहीं दी गई है। कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल संभव होगा। पेस्टीसाइड के स्प्रे करने के अलावा ड्रोन का खेतों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने पर भी क्या अनुमति लेनी होगी। इस तरह का इस्तेमाल करने से 24 घंटे पहले स्थानीय थाने को जानकारी देनी होगी। इसके तहत 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। ड्रोन को उड़ाने की अनुमति सिर्फ दिन में है। रात में इसके इस्तेमाल के लिए डीजीसीए से अनुमति लेनी होगी।

ड्रोन उड़ाने के लिए तीन अलग-अलग जोन्स हैं:

रेड जोन- इसमें ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है

येलो जोन- इसमें तय सीमा में उड़ाने की अनुमति मिलेगी

ग्रीन जोन- इसमें ऑटोमैटिक अनुमति मिल जाएगी

ड्रोन्स को भार के आधार पर 5 अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है:

- नैनो- 250 ग्राम तक
- माइक्रो- 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक
- स्मॉल- 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक
- मीडियम- 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक
- लार्ज- 150 किलोग्राम से अधिक

कितना आएगा खर्च?

- यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानि की UIN के लिए 1,000 रुपये फीस लगेगी
- परमिट इश्यू करने के लिए 25,000 रुपये की फीस लगेगी
- परमिट रिन्यू करवाने के लिए 10,000 रुपये की फीस लगेगी।

जट्रोफा फसल से बने बॉयो ईंधन से देश में पहली बार उड़ा जहाज

तय की देहरादून से दिल्ली की दूरी

नई दिल्ली।एजेंसी

सस्ती उड़ान सेवा देने वाली कंपनी स्पाइसजेट ने देश की पहली जैव जेट ईंधन से चलने वाली परीक्षण उड़ान का परिचालन किया। बॉम्बार्डियर क्यू 400 विमान के जरिये इस उड़ान का परिचालन किया गया और इसमें आंशिक रूप से जैव जेट ईंधन का इस्तेमाल किया गया। देहरादून से रवाना होकर यह उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। एयरलाइन ने कहा कि उसने पहली जैव जेट ईंधन की उड़ान का सफलता से परिचालन पूरा किया। इस उड़ान के लिए इस्तेमाल ईंधन 75 प्रतिशत एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) और 25 प्रतिशत जैव जेट ईंधन का मिश्रण था। एयरलाइन में

परीक्षण उड़ान पर करीब 20 लोग सवार थे. इनमें नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और स्पाइसजेट के अधिकारी शामिल रहे. एयरलाइन के एक अधिकारी ने बताया कि यह उड़ान करीब 25 मिनट की थी. स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि जैव जेट ईंधन की लागत कम बैठती है और साथ ही यह उल्लेखनीय रूप से कॉर्बन उत्सर्जन घटाने में मदद करता है।

बयान में कहा कि एटीएफ की तुलना में जैवजेट ईंधन इस्तेमाल का फायदा यह है कि इससे कॉर्बन उत्सर्जन घटता है और साथ ही ईंधन दक्षता भी बढ़ती है।

स्पाइसजेट ने कहा कि जट्रोफा फसल से बने इस ईंधन का विकास सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून ने किया है.

उन्होंने कहा, "इसमें हमारी परंपरागत विमान ईंधन पर प्रत्येक उड़ान में निर्भरता में करीब 50 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है। इससे किराये में भी कमी आएगी. जैव जेट ईंधन को अमेरिकी मानक परीक्षण प्रणाली (एएसटीएम) से मान्यता है और यह विमान में प्रैट एंड व्हिटनी तथा बॉम्बार्डियर के वाणिज्यिक एप्लिकेशन के मानदंडों को पूरा करता है। क्यू400 विमान में 78 सीटें हैं। एयरलाइंस कंपनियों के वैश्विक निकाय आईएटीए के अनुसार वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में विमानन उद्योग का हिस्सा दो प्रतिशत बैठता है।

नोटबंदी के दौरान अमान्य की गई करेंसी का 99.30 फीसद हिस्सा सिस्टम में लौटा: RBI रिपोर्ट

नई दिल्ली । नोटबंदी के बाद अमान्य की गई करेंसी लगभग-लगभग रिजर्व बैंक के सिस्टम में वापस लौट चुकी है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय बैंक की सालाना रिपोर्ट में यह बात कही गई है। गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी, जिसके बाद 9 नवंबर से ही 500 और 1000 रुपये के नोट अमान्य कर दिए गए थे। ये उस वक्त बाजार में प्रचलित कुल मुद्रा का 86 फीसद हिस्सा थे।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि 500 और 1000 रुपये के अमान्य किए जा चुके नोटों की प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है और करीब 99.30 फीसद अमान्य नोट सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। 8 नवंबर 2016 (नोटबंदी की घोषणा वाले दिन) तक अमान्य नोटों की कुल वैल्यू 15.42 लाख करोड़ रुपये थी और इनमें से 15.31 लाख करोड़ रुपये आरबीआई के सिस्टम में लौट चुके हैं।

मार्च 2018 तक बाजार में उपलब्ध नोटों की वैल्यू 37.7 फीसद बढ़कर 18,037 बिलियन रुपये के स्तर तक पहुंच गई। बैंक नोटों की संख्या में हालांकि 2.1 फीसद का ही इजाफा हुआ है। अगर सिर्फ 500 और 2000 रुपये के नोटों की बात करें तो मार्च 2017 तक बाजार में उपलब्ध कुल नोटों में इनकी हिस्सेदारी 72.7 फीसद थी। गौरतलब है कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य करार दे दिया था, हालांकि सरकार ने इन्हें नए नोटों से बदलवाने के लिए लोगों को कुछ वक्त भी दिया था।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्प्लेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।